RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 मुंबई : गुरुवार 14 दिसंबर 2023 वर्ष 05 अंक 232 संपादक : फैसल शेख पृष्ठ : 4 कीमत : 03 रुपये

दैनिक
रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

नई संसद की सुरक्षा में चूक के बाद
महाराष्ट्र में अलर्ट !
शीतकालीन सत्र के लिए डिप्टी चेयरमैन ने लिया बड़ा फैसला...

नागपुर में चल रहा है राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र

नागपुरः नई पार्लियामेंट की सुरक्षा में चूक सामने के बाद महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विजिटर पास नहीं बनेंगे। महाराष्ट्र विधान परिषद की उप सभापति नीलम गोरहे ने दो लोगों के लोकसभा की दर्शक दीर्घा में कूदकर धुआं फैलाने की घटना के मद्देनजर

अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे आगंतुकों को परिषद की दर्शक दीर्घा के लिए पास जारी न करें। इन दिनों नागपुर में राज्य विधान मंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि विधान परिषद् के साथ विधानसभा में विजिटर पास बंद किया जा सकता है। नई संसद में सुरक्षा चूक का यह मामला पार्लियामेंट अटैक की बरसी पर सामने आया है। इसको लेकर विपक्ष हमलावर भी है।

उद्धव गुट ने उठाया सदन में मामला

सूत्रों के अनुसार घटना के बाद गोरहे ने संबंधित अधिकारियों को परिषद की दर्शक दीर्घा के लिए पास जारी नहीं करने के निर्देश दिए। विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने लोकसभा में हुई इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि वहां क्या हुआ। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि राज्य सरकार इस पृष्ठभूमि में क्या सावधानियां बरत रही है। उद्योग मंत्री उदय सामंत ने सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा कि यह लोकसभा बताएगी कि वास्तव में वहां क्या हुआ था। सामंत ने कहा कि राज्य सरकार सभी आवश्यक सावधानियां बरतेगी और वह विधानमंडल में विधायकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम है। पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने विधानमंडल परिसर में संवाददाताओं से बात करते हुए लोकसभा की घटना को डरावनी बताया और मांग की कि सरकार यहां विधान भवन में उचित सुरक्षा सुनिश्चित करे।

संसद की कार्यवाही करनी पड़ी थी स्थगित

संसद पर आतंकवादी हमले की 22वीं बरसी पर बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा से दो लोग सदन के भीतर कूद गए और उन्होंने केन के जरिए धुआं फैलाया तथा नारेबाजी की जिसके बाद कार्यवाही अचानक दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। घटना के तत्काल बाद दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। इसी समय नयी दिल्ली में संसद परिसर के बाहर एक महिला समेत दो लोगों ने पीले और लाल रंग का धुआं छोड़ने वाली केन लेकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि सदन में कूदने वाले दोनों लोगों को पकड़ कर उनके पास से सारी सामग्री जब्त कर ली गई है तथा संसद भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे दो लोगों को भी पकड़ा गया है।

महाराष्ट्र में स्कूल के शिक्षकों का आपत्तिजनक वीडियो वायरल,
परिसर के अंदर किया गंदा काम, मचा हड़कंप

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र के बीड के एक स्कूल के शिक्षकों का आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया है। आपत्तिजनक वीडियो स्कूल के परिसर का है। वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल अधिकारियों और अभिभावकों ने नाराजगी जाहिर की है। हर कोई इस घटना से हैरान है। अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान में टीचर के रूप में काम करने वाले एक पुरुष और महिला टीचर परिसर में गंदा काम किया और इसका वीडियो शूट किया।

शिकायत में कहा गया है कि ये वीडियो वायरल किए गए थे। दरअसल, स्कूल के चपरासी ने अधिकारियों को 15 नवंबर की घटना के बारे में जानकारी दी। तब तक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

हो चुका था। इसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने वाले शख्स और अन्य के खिलाफ 9 दिसंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

मुख्य आरोपी हुआ फरार

शिकायत के आधार पर बीड शहर पुलिस ने पुरुष शिक्षक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 292 (2) (अश्लील सामग्री), धारा 294 (अश्लीलता), धारा 500 (मानहानि) और सूचना प्रौद्योगिकी के कई प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की है।

मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन में लगी भीषण आग,
यात्रियों को स्टेशन से निकाला गया बाहर

मुंबई : मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस रेलवे स्टेशन की जन आहार कैंटीन में बुधवार दोपहर को भीषण आग लग गई। हादसे में फिलहाल किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। सेंट्रल रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि घटना के कारण कुछ ट्रेनों के परिचालन में देरी हुई। घटना के वक्त स्टेशन के वेटिंग एरिया और प्लेटफार्म पर सैकड़ों यात्री मौजूद थे। सभी यात्रियों को वक्त रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अग्निशमन वाहन के अलावा, मुंबई पुलिस, रेलवे के अधिकारी और आरपीएफ सहित विभिन्न एजेंसियों के कर्मी मौके पर जुटे हुए थे। आग पर घंटे भर के अंदर काबू पा लिया गया।

अंतरराज्यीय ड्रग तस्कर लक्ष्मीकांत प्रधान गिरफ्तार...
मुंबई पुलिस ने 3.85 करोड़ के गांजे के साथ पकड़ा

मुंबई : मुंबई क्राइम ब्रांच ने मोस्ट वॉन्टेड अंतरराज्यीय ड्रग तस्करी के मुख्य आरोपी लक्ष्मीकांत प्रधान और उसके सह-सहयोगी बिद्याधर बृंदाबन प्रधान को 1820 किलोग्राम गांजा मामले में ओडिशा के गंजम जिले से गिरफ्तार किया है। इस गांजे की कुल कीमत 3.85 करोड़ रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान पता चला कि, तस्करी का सामान ओडिशा से ही खरीदा गया था। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने ओडिशा और आंध्र प्रदेश में मोस्ट वॉन्टेड तस्करों की तलाश शुरू की। गिरफ्तारी से बचने के लिए तस्कर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विभिन्न इलाकों में घूमता पाया गया।

करीबन एक महीने की कोशिश के पास पुलिस को मुख्य तस्कर क्ष्मीकांत प्रधान और उसके सह-सहयोगी बिद्याधर बृंदाबन प्रधान के ओडिशा में होने की जानकारी मिली। मुंबई से एक टीम आरोपियों को पकड़ने के लिए रवाना हुई। दोनों आरोपियों को फिलहाल ट्रांजिट रिमांड पर ओडिशा लाया गया है। उनके अलावा अन्य तस्करों की तलाश फिलहाल जारी है।

ठाणे में 'एमएमआरडीए' निधि वर्ष, विभिन्न परियोजनाओं के लिए 1300 करोड़

नागपुर: मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की मंगलवार को हुई बैठक में करीब 1300 करोड़ रुपये की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी गई.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में मंगलवार को 'एमएमआरडीए' की बैठक हुई. बैठक में कुर्ला में डेयरी विकास विभाग की लगभग 10.46 हेक्टेयर भूमि और वर्ली में 6.40 हेक्टेयर भूमि प्राधिकरण को निःशुल्क हस्तांतरित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार से 'एमएमआरडीए' को योजना प्राधिकरण नियुक्त करने का अनुरोध करने वाले एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। राज्य सरकार से प्राधिकरण के माध्यम से विकासकर्ता के रूप में घाटकोपर में रमाबाई अंबेडकर नगर स्लम पुनर्विकास योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी देने का अनुरोध किया गया है।

ठाणे और बोरीवली के बीच जुड़वां सुरंग के निर्माण के लिए आवश्यक धन जुटाने की मंजूरी दी गई। ठाणे शहर में रेलादेवी झील का 60.24 करोड़ रुपये की लागत से सौंदर्यीकरण किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि कपूरबावड़ी और गायमुख के बीच ठाणे-घोड़बंदर मार्ग पर मुख्य और सर्विस सड़कों को मिलाकर 559.27 करोड़ रुपये खर्च करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. ठाणे और मेट्रो के आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न मेट्रो मार्गों के लिए मोगरपाड़ा में एक कारशेड स्थापित किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए अधिकृत किसानों को अधिग्रहित भूमि का 22.5 प्रतिशत और विकसित भूमि का 12.5 प्रतिशत भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। अतिक्रमण करने वाले किसान.

विस्तारित मुंबई शहरी बुनियादी ढांचा परियोजना के तहत, मनकोली-मोथागांव एक्सप्रेसवे और डोंबविली और भिवंडी शहरों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच जंक्शन पर 57.67 करोड़ रुपये का सबवे बनाया जाएगा। कल्याण-डोंबिवली नगर निगम क्षेत्र में वालधुनी नदी के समानांतर 24 मीटर चौड़ी सड़क और मुरबाड रोड, बदलापुर रोड और पुणे लिंक रोड को जोड़ने वाले दो फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 642 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कर्जत से हाल फाटा सड़क कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 100 करोड़, मुंबई-गोराई रोड पर बनने वाले खादी पुल और एप्रोच रोड के लिए 888 करोड़ रुपये। 84 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है.

संपादकीय / लेख

370 हटाना संवैधानिक

सर्वोच्च अदालत की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की संवैधानिकता पर मुहर लगा दी। संविधान पीठ ने इस संदर्भ में राष्ट्रपति के आदेश, मोदी सरकार के फैसले और संसद के दो-तिहाई बहुमत के निर्णय को वैध करार दिया है। अदालत ने स्थापित किया है कि अनुच्छेद 370 कभी भी संविधान का स्थायी प्रावधान नहीं था। वह अस्थायी व्यवस्था थी, क्योंकि उस समय युद्ध के हालात थे। जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह की उद्घोषणा और भारत में विलय के बाद जम्मू-कश्मीर की कोई संप्रभुता नहीं रही। अनुच्छेद 370 के तहत कोई आंतरिक संप्रभुता भी नहीं थी। जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया था। यह संविधान के अनुच्छेद एक से भी स्पष्ट है। अनुच्छेद 370 ने कश्मीर को एक अलग संविधान, अलग ध्वज और आंतरिक प्रशासनिक स्वायत्तता रखने का अधिकार दिया था, जबकि यह राज्य 1952 से 31 अक्तूबर, 2019 तक एक राज्य के रूप में भारत और उसके संविधान द्वारा ही शासित था। देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में संविधान पीठ ने एकमत से अनुच्छेद 370 पर ऐतिहासिक फैसला सुनाकर सभी 23 याचिकाओं, कुतर्कों, भ्रांतियों और संविधान सभा की गलत व्याख्याओं को खारिज कर दिया। हालांकि तीन अलग-अलग फैसलों में विचार भी भिन्न थे, लेकिन अनुच्छेद 370 पर पांचों न्यायाधीश एकमत थे। अब कश्मीर पर हर भारतीय का संवैधानिक हक है। 5 अगस्त, 2019 को राष्ट्रपति के जिस आदेश पर संसद में बहस हुई और अंततः अनुच्छेद 370 के अस्तित्व को समाप्त किया गया, उसके परिप्रेक्ष्य में संविधान पीठ ने साफ कहा है कि राष्ट्रपति को राज्य की संविधान सभा की गैर-मौजूदगी में भी इसे रद्द करने का अधिकार था। संविधान सभा राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं थी। राष्ट्रपति ने किसी भी दुर्भावना के तहत अपनी शक्ति का उपयोग नहीं किया। संविधान पीठ राष्ट्रपति के निर्णय के खिलाफ किसी भी अपील की सुनवाई नहीं कर सकती।

सारांश यह है कि अब जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में अनुच्छेद 370 और विशेष दर्जे का कोई अस्तित्व नहीं है। वह भी देश के अन्य राज्यों की तरह, भारत के संविधान, संसद और सरकार द्वारा, शासित और संचालित है। केंद्र सरकार यथाशीघ्र कश्मीर का राज्यत्व बहाल करेगी। चुनाव आयोग 30 सितंबर, 2024 तक वहां चुनाव कराए। जम्मू-कश्मीर के हर नागरिक पर भारतीय कानून लागू होंगे। साथ ही, हर भारतीय को कश्मीर में वे सभी अधिकार मिलेंगे, जो शेष देश में मिलते रहे हैं। बेशक संवैधानिक तौर पर अनुच्छेद 370 का मामला अब इतिहास के पन्नों में समा गया है, लेकिन अब भी कुछ राजनीतिक दल और चेहरे इसे 'काला दिन', निराशाजनक अध्याय और गलत फैसला करार दे रहे हैं। उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखने के ऐलान भी किए हैं। आखिर किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है? संविधान पीठ का फैसला अंतिम संवैधानिक फैसला है। संसद अपने फैसले पर 2019 में ही मुहर लगा चुकी है। लोकतंत्र में और क्या विकल्प संभव हैं? यह 'सियासी कुंठा' के अलावा कुछ भी नहीं है। पुनर्विचार याचिकाओं का हश्र भी यही होना है। बहरहाल इस ऐतिहासिक फैसले के बाद टीवी चैनलों पर आम कश्मीरी थाली बजाते, नाचते-गाते, मिष्ठान्न खिलाते जश्न के मूड में दिखाई दिए। 'ऐतिहासिक लाल चौक' का बाजार भी पूरी तरह खुला है। तथ्य संसद में पेश किए गए हैं कि कश्मीर में 200 से ज्यादा विदेशी निवेशकों को जमीनें दी गई हैं। अर्थव्यवस्था चार गुनी हो गई है। गरीबों के लिए 5 साल में 1.45 लाख घर बन चुके हैं। नई विधानसभा में कुछ आरक्षण तय हुआ है।

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)
+91 99877 75650
editor@rokthoklekhaninews.com
Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

मराठी फिल्मों को थियेटर उपलब्ध ना होने को लेकर नागरपुर अधिवेशन मे उठा मुद्दा

एक बार येऊ तरी बागा के मराठी कलाकारों ने मनसे अधक्ष्य राजठाकरे माउली थोर्वे व्यक्त आभार

चेंबूर विभाग अधक्ष्य माऊली थोर्वे ने किया के स्टार माल मे मुफ्त महिलाओ के लिए शो आयोजित

मुंबई (फिरोज सिद्दीकी) राज्य मे मराठी फिल्म एकदा येऊन तर बघा मराठी फिल्मों को थियेटर उपलब्ध ना होने का मुद्दा गर्मने के कारण नागरपुर अधिवेशन मे उठा मुद्दा । जिसमें प्रवीण दरेकर ने मुद्दा उठाते दिखाई दिये। दूसरी ओर राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नाविस ने कड़े शब्दों मे कहा की जो मल्टी प्लेक्स मालिक माराठी फिल्मों को स्क्रीन उपलब्ध नहीं करवायेंगे उनके उपर कड़ी करवाई की जायेगी।

एक बार येऊ तरी बागा मराठी फिल्म को मानसे की धमकी के कारण मुंबई के 45 मल्टीप्लेक्स थियेटर मालिको ने मनसे की धमकी से डर कर स्क्रीन उपलब्ध करवाई । जिस्को लेकर एक बार येऊ तरी बागा के मराठी कलाकारों ने मनसे अधक्ष्य राज ठाकरे, माउली थोर्वे का माना आभार । गौरतलब हो की मनसे अधक्ष्य राजठकरे द्वारा दुबारा से इस मुद्दे को

उठाने से मनसे अक्रामक हो गई ।

चेंबूर विभाग अधक्ष्य माऊली थोर्वे ने किया मुफ्त मे महिलाओ के लिए शो किया आयोजित वहीं मनसे चेंबूर विभाग अधक्ष्य माउली थोर्वे ने चेंबूर के स्टार माल मे महिलाओ के लिए एक विशेष प्राइम टाइम शो की व्यवस्था करवाई थी। माउली थोर्वे के इस प्रयास से प्राइम टाइम का शो हाउस फूल गया । दूसरी ओर मनसे की चेंबूर सहित अन्य अगल बगल के विधानसभा मे बढ़ती लोकप्रियता का सारा श्रेय राज ठाकरे के बाद चेंबूर विभाग प्रमुख माउली थोरवे को जाता है । ऐसा स्थानीय कट्टर मन सैनिकों सहित स्थानीय जनता का ऐसा मानना है।

मनसे अधक्ष्य राज ठाकरे का मल्टी प्लेक्स मालिको ने किया

अमल बजवानी –

बताते है की चेंबूर विभाग प्रमुख माउली थोरवे नेतृत मे मनसे सैनिकों ने चेंबूर के स्टार माल के मैनेजर को लिखित मे ज्ञापन देकर नेक्स्ट शो मराठी फिल्म एक बार येऊ तरी बागा को स्क्रीन न सिर्फ चेंबूर के मल्टी प्लेक्स मे मिली बल्की संपूर्ण मुंबई के मल्टी प्लेक्स थियेटर मालिको ने राज ठाकरे के मराठी फिल्मों को स्क्रीन देने के आदेश को लागू किया। जिसको लेकर मनसे कार्यकर्ताओ मे उत्साह व्यक्त है।

महाराष्ट्रा मे सिर्फ भूमि पुत्रो का राज होगा –

वहीं दूसरी ओर माउली थोरवे ने कहा की मराठी भूमि पुत्रो की हक के लिय लड़ने वाली सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है वो है मनसे। मनसे और राज्य साहेब ठाकरे को एक बार महाराष्ट्रा की सत्ता पर काबिज कर के देखो राज्य मे विकास की बयार चलेगी।

महाराष्ट्र सदन तक पहुंची धारावी पुनर्विकास परियोजना...

मुंबई : एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी-बस्ती धारावी के पुनर्विकास परियोजना का विरोध मुंबई की सड़कों से आगे बढ़कर महाराष्ट्र विधानमंडल तक पहुंच गया। महाराष्ट्र के विपक्षी दलों के सदस्यों ने धारावी पुनर्विकास परियोजना में अदाणी समूह का पक्ष लेने तथा झुग्गीवासियों को मंझधार में छोड़ देने का सरकार पर आरोप लगाया। शिवसेना (उद्धव) इस परियोजना के विरोध में 16 दिसंबर को सड़क पर उतरने की घोषणा कर चुकी है। नागपुर में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान आज विपक्षी दलों विधानभवन की सीढ़ियों पर इस मुद्दे को लेकर नारेबाजी की। उनके नारों में एक धारावी वाचवा, लघु उद्योग वाचवा (धारावी बचाओ, लघु उद्योग बचाओ) का नारा था।

विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि सरकार धारावी की जमीन अदाणी को उपहार में दे रही है। लेकिन झुग्गियों में लघु उद्योग चला रहे कई लोग इस प्रकिया में प्रभावित हो रहे हैं। शक है कि धारावी में 70000 से अधिक लोगों को वहां मकान मिलेगा या नहीं। इसी तरह टीडीआर का स्वामित्व भी अदाणी समूह को दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए हमने विधान भवन की सीढ़ियों पर प्रदर्शन किया। विपक्षी महा विकास आघाड़ी (एमवीए) इस मुद्दे को विधानमंडल के दोनों सदनों में उठाएगी।

धारावी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहीं मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि धारावी का पुनर्विकास स्थानीय लोगों के फायदे के लिए होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ रुपये के वार्षिक कारोबार वाले छोटे उद्योग धारावी में चल रहे हैं। निविदा में कहा गया है कि धारावी के लोगों को वर्तमान झुग्गी बस्ती से 10 किलोमीटर दूर स्थानांतरित किया जाएगा। टीडीआर एक बड़ा घोटाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीडीआर एक बहुत बड़ा घोटाला है। विपक्षी दल कांग्रेस सरकार पर धारावी पुनर्विकास परियोजना के नियमों में ढील देकर अदाणी समूह को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया रही है।

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के मध्य में स्थित धारावी कई छोटे असंगठित उद्योगों का केंद्र है जहां दवा, चमड़ा, जूते और कपड़े जैसी वस्तुओं का विनिर्माण होता है। यह एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में एक के रूप में भी जाना जाता है।

मुंबई सौंदर्यीकरण योजना, 700 करोड़ रुपए खर्च

मुंबई : सौंदर्यीकरण योजना के अंतर्गत सड़कों का कंक्रीटीकरण, पुलों के नीचे थीम बेस एलईडी एलिमिनेशन, फुटपाथ का नूतानीकरण, सड़क के बीच डिवाइडर लगाना, ट्रैफिक आइलैंड इत्यादि का काम करने का पैष्ठसला लिया गया था। इन सब कामों के लिए करोड़ों के फंड भी आावंटित किए गए थे। फुटपाथ के लिए ९७ करोड़ रुपए, सड़क के लिए १४० करोड़, बांद्रा किले के आस-पास की जगह के सौंदर्यीकरण के लिए १२.५७ करोड़ रुपए और अन्य कामों के लिए ५० करोड़ की रकम आवंटित की गई थी। सौंदर्यीकरण के अंतर्गत ही जगह जगह चौक पर अलग-अलग थीम पर मूर्तियां, एलईडी लाइट आादि लगाए गए थे। रात्रि के समय हर जगह उजाला रहे और आकर्षक दिखाई दे इसलिए बहुत सारे जगह इलेक्ट्रिक पोल पर एलईडी लाइट लगाए गए और वृक्षों पर भी लाइट के झालर लगाए गए।

पालघर/ आंगनवाड़ी केंद्र बंद होने से लाभार्थी पोषाहार से वंचित...

पालघरः आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 4 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है. आंगनवाड़ी कार्यकताओं की हड़ताल के कारण आंगनबाड़ियों में आने वाले छात्र और स्तनपान कराने वाली माताएं पोषण आहार से वंचित हैं। आंगनबाड़ियों के बंद होने से छात्रों की भीड़ लग जाती है और देखा जा रहा है कि इससे उनके पोषण पर काफी असर पड़ रहा है. आंगनबाडी कार्यकताओं को मिलने वाले अल्प पारिश्रमिक, पेंशन, ग्रेच्युटी आदि मांगों को लेकर आंगनबाडी कार्यकताओं और कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है। पालघर जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वर्षों से अल्प पारिश्रमिक पर अपना कर्तव्य निभा रही हैं। हालाँकि, उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल रहा है और पोषण के लिए सब्सिडी भी समय पर नहीं मिलने के कारण उन्हें अपने खर्च से भोजन खरीदने के बाद 4 से 5 महीने तक सब्सिडी का इंतजार करना पड़ता है। नतीजा यह हुआ कि जिले की सात हजार आंगनबाडी सेविकाएं हड़ताल में शामिल हो गयीं और इस कारण फिलहाल आंगनबाडी केंद्र बंद रहने से लाभुकों को सरकारी योजना के लाभ से वंचित होना पड़ा. जिले में कई आंगनबाडी केन्द्रों के पास अपनी जगह नहीं है और कई आंगनबाडी केन्द्रों के जर्जर होने के कारण यह देखा गया है कि कई आंगनबाडी केन्द्र घरों, घरों के बाहर और ग्राम समुदाय के मंदिरों में भर रहे हैं। आंगनबाडी सेविकाएं मांग कर रही हैं कि ऐसे आंगनबाडी केंद्र उपलब्ध कराए जाएं। पालघर जिले को कुपोषित जिले के रूप में जाना जाता है। जिले के विक्रमगढ़, जव्हार और मोखाडा तालुका में कुपोषण दर अधिक है। ऐसी आशंका है कि अगर इस क्षेत्र के लाभार्थियों को समय पर उचित पोषण नहीं मिला तो कुपोषण की दर बढ़ जाएगी। इसके अलावा, इस क्षेत्र में बेरोजगारी और गरीबी की उच्च दर के कारण, अधिकांश परिवार स्वस्थ भोजन खरीदने की क्षमता की कमी के कारण सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन पर निर्भर हैं।

हमारे स्तर से केंद्र शुरू करने का निर्देश आंगनबाडी सेविकाओं को दिया गया है. लेकिन वे अपनी मांगें पूरी होने तक केंद्र शुरू करने से इनकार कर रहे हैं. जब हमने अपने स्तर से विभिन्न संस्थाओं से स्वास्थ्यवर्धक एवं पौष्टिक भोजन पकाने का अनुरोध किया तो उनसे हमें उचित जवाब नहीं मिला। चूंकि आंगनबाडी सेविकाओं की मांगों को पूरा करना हमारा अधिकार है, इसलिए वरिष्ठ स्तर से उचित निर्णय लिया जायेगा. - प्रवीण भावसार, जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी।

अस्पतालों में हुई मौतों का मुद्दा... विपक्ष ने ऑक्सिजन मास्क पहनकर किया प्रदर्शन

नागपुरः विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन नागपुर की ठंड में गरमाहट भरा रहा। जहां उद्योग मंत्री उदय सामंत ने बीएमसी के पिछले 25 साल के वित्तीय लेन-देन के ऑडिट के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की, वहीं राज्य के अस्पतालों में हो रहीं मौतों के विरोध में विपक्ष ने ऑक्सिजन मास्क पहनकर प्रदर्शन किया। साथ ही दिशा सालियान की मौत के मामले की जांच के लिए एसआईटी के गठन की घोषणा भी की गई। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आनंद निगुर्डे (सेवानिवृत्त) का मामला भी सदन के अंदर और बाहर गूंजा। उद्धव ठाकरे ने इसकी भी एसआईटी जांच की मांग की। वित्तमंत्री अजित पवार ने पुरानी पेंशन योजना के बाबत भी विधानसभा चुनाव से पहले निर्णय लेने की घोषणा की। मराठा आरक्षण का मामला भी चर्चा में रहा। सरकारी अस्पतालों की बदहाली पर विपक्ष ने सरकार का ध्यान खींचा। आरोप लगाया कि स्वास्थ्य सेवाएं 'वेंटिलेटर' पर हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार, विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे, काग्रेस नेता अशोक चव्हाण, बालासाहेब थोरात व अन्य ने सफेद कोट पहने, स्टेथोस्कोप और स्ट्रेचर लेकर विधान भवन के बाहर सीढ़ियों पर नारेबाजी की। दानवे ने कहा कि नागपुर, नांदेड़, छत्रपति संभाजीनगर और ठाणे जिले के कलवा के सरकारी अस्पतालों में लापरवाही से कई मौतें हुई हैं। विधानसभा में एक चर्चा के दौरान उद्योग मंत्री उदय सामंत ने मुंबई मनपा के पिछले 25 साल के वित्तीय लेनदेन की जांच के लिए समिति गठित करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बीएमसी में घोटाला होने के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसकी जांच आवश्यक है। उनसे जब पूछा गया कि क्या नागपुर, पुणे, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली सहित अन्य मनपा में भी ऐसी जांच की जाएगी? इस पर सामंत ने कहा कि ऐसी जांच की मांग करने का कोई कारण नहीं है।

महाराष्ट्र में कैंसर के सबसे ज्यादा मामले

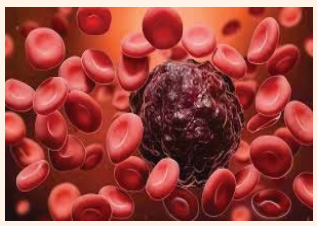

मुंबईः महाराष्ट्र में वर्ष 2022 के दौरान कैंसर के उपचार के लिए औसतन 333 लोगों का रोजाना रजिस्ट्रेशन किया गया है। नैशनल कैंसर रजिस्ट्री और स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा कैंसर मरीज महाराष्ट्र में रजिस्टर हुए हैं। साल 2013 में कैंसर से महाराष्ट्र में 97,759 लोग ग्रसित हुए थे, जबकि वर्ष 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर 1,21,717 हो गया। पिछले एक दशक के दौरान राज्य में कैंसर के मरीजों की संख्या 24 फीसदी तक बढ़ी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च-नैशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम (आईसीएमआर-एनसीआरपी) के अनुसार, कैंसर के मामलों की अनुमानित संख्या साल 2022 में 14.61 लाख थी, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 15.7 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। एनसीआरपी के आंकड़ों के अनुसार, देशभर में कैंसर के कुल 11,67,429 मामले दर्ज हुए हैं। सबसे अधिक 1,70,242 मामले यूपी से हैं, जबकि महाराष्ट्र से 97,759 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वर्ष 2022 में देशभर में कुल 14,61,427 कैंसर के केस सामने आए थे। तब यूपी से 2,10,958 और महाराष्ट्र से 1,21,717 मामले रिपोर्ट हुए थे।

चौक-चौराहों पर बैनरबाजी पर सख्त प्रतिबंध... बैनर लगानेवालों पर होगी कार्रवाई !

ठाणे : ठाणे मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर ने शहर की सुंदरता को बरकरार रखने के लिए शहर में मेट्रो के पिलरों और ट्रैफिक सिग्नलों, चौक-चौराहों पर बैनरबाजी पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। अब बैनरबाजी करनेवालों पर ठाणे मनपा द्वारा दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। दरअसल, बैनरबाजी के कारण शहर की सुंदरता पर ग्रहण लग जाता है।

मनपा क्षेत्र में प्रत्येक बुधवार को अवैध बैनरों को लेकर सफाई अभियान चलाया जाएगा। तीनों मंडलों के उपायुक्त और सभी वार्ड समितियों के सहायक आयुक्त अपनी सीमा में यह अभियान चलाएंगे।

शहर में ट्रैफिक चौक जो यातायात को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाए गए हैं। उन चौकों पर हर जगह बैनर लगे हुए दिखाई देते हैं। ये बैनर यातायात को बाधित करते हैं साथ ही शहर को बदसूरत बनाता है। इसलिए सभी सहायक आयुक्त यह सुनिश्चित करें कि इन यातायात चौकों पर किसी भी स्थिति में बैनर न लगाए जाएं, ऐसा निर्देश मनपा आयुक्त ने सभी सहायक आयुक्तों को दिया है। मेट्रो के खंभों पर चिपकाए गए विज्ञापन पूरे शहर में खराब छवि बनाते हैं। शहर का सौंदर्यीकरण कर ठाणे की सूरत बदलने का प्रयास किया जा रहा है। इनमें सबसे ज्यादा दिक्कत मेट्रो के खंभों पर लगे बैनरों से होती है। फिलहाल मेट्रो के खंभों पर पेंटिंग का काम चल रहा है साथ ही मेट्रो के नीचे के इलाकों में पार्क, बैठने की व्यवस्था, सौंदर्यीकरण के काम शुरू हो गए हैं।

लाखों रुपयों की लागत से बने सेल्फी पॉइंट मात्र एक महीने में बर्बाद!

मुंबई : लाखों रुपए खर्च कर स्टेशनों पर बनाए गए सेल्फी पॉइंट्स को मध्य रेलवे की तरफ से हटाया जा रहा है। रेलवे स्टेशनों पर बनाए गए सेल्फी पॉइंट केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार करने का जरिया बन गए थे। लाखों रुपयों की लागत से बने ये सेल्फी पॉइंट मात्र एक महीने में ही बर्बाद हो गए। ऐसे में रेलवे अधिकारियों के साथ-साथ यात्रियों के बीच भी इस बात की चर्चा है कि रेलवे का लाखों रुपया पानी में डूब गया। गौरतलब है कि रेलवे बोर्ड ने निर्देश दिया था कि रेलवे अपने सेक्शन में कम से कम २० सेल्फी पॉइंट बनाए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया था कि प्रत्येक सेल्फी प्वाइंट पर कम से कम डेढ़ लाख रुपये खर्च किये जाने चाहिए।

इसी के तहत रेल प्रशासन ने अपने सेक्शनों में सेल्फी प्वाइंट बनाये थे। रेलवे बोर्ड की ओर से करीब छह लाख रुपयों की लागत से श्रीडी सेल्फी प्वाइंट भी लगाने का निर्देश दिया गया था। जिसके बाद रेलवे अधिकारियों ने भी बोर्ड के आदेश का पालन करते हुए काफी पैसे खर्च कर स्टेशन के प्लेटफार्म पर सेल्फी प्वाइंट बनाए थे। लेकिन यात्रियों में इसे लेकर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिलने के कारण इन्हें बंद किया जा रहा है। मध्य रेलवे ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर चार-पांच सेल्फी पॉइंट भी स्थापित किए थे, लेकिन रेलवे ने अब इसे खत्म कर दिया है।

अंधेरी-कुर्ला मार्ग पर फेरीवालों ने कर लिया कब्जा !

मुंबई : नीति तय होनी चाहिए कि फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए हैं या फेरीवालों के लिए। अंधेरी-कुर्ला मार्ग पर फेरीवालों की संख्या बढ़ गई है और इस मार्ग पर नगर निगम द्वारा बनाए गए फुटपाथ पर फेरीवालों ने कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, सड़क की दो लेन पर भी रेहड़ी-पटरी वालों का कब्जा हो गया है। इस इलाके में फेरीवालों ने सड़कों पर धंधा लगाकर नागरिकों का रास्ता बंद कर दिया है। इससे यहां के नागरिक बेहद नाराज हैं। सोशल मीडिया पर नागरिक शिकायत कर रहे हैं कि मुंबई में हर जगह फेरीवालों की संख्या एक बार फिर बढ़ गई है। पिछले कुछ दिनों में अंधेरी-कुर्ला रूट पर फेरीवालों की संख्या काफी बढ़ गई है। मुंबई की सड़कों पर प्रवासी फेरीवालों का भी कब्जा हो गया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि नगर निगम के संबंधित अधिकारियों की मदद के बिना फेरीवालों की संख्या इतनी नहीं बढ़ सकती। जे.बी. नगर में प्रत्येक शनिवार को बाजार लगता है। उस समय रेहड़ी-पटरी वालों की भीड़ के बीच से पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। रेहड़ी-पटरी वालों ने पूरे फुटपाथ पर कब्जा कर लिया है, इससे खरीदारों की भीड़ भी बढ़ रही है। इसके चलते अंधेरी-कुर्ला रोड पर दो लेन वाहनों के लिए जगह नहीं छोड़ी गई है।

एसटी में डिजिटल पेमेंट की पहल; यूपीआई, क्यूआर कोड सुविधा उपलब्ध

मुंबई : राज्य परिवहन निगम (एसटी) की बसों में यात्रा करते समय यात्रियों और कंडक्टरों के बीच अक्सर छुट्टे पैसों को लेकर बहस हो जाती है। लेकिन अब एसटी कॉर्पोरेशन ने टिकटों को 'डिजिटल' कर दिया है। एसटी यात्रियों के लिए डिजिटल टिकट जारी करने वाली मशीनें एटीआईएम खरीदी गई हैं। इन मशीनों से यात्री यात्रा के दौरान नकद लेनदेन से बच सकेंगे और यूपीआई, क्यूआर कोड के माध्यम से 'डिजिटल भुगतान' का उपयोग करके टिकट खरीद सकेंगे। 'वैष्ठशलेस इंडिया' की तर्ज पर हर सेक्टर में डिजिटल पेमेंट करने की पहल की जा रही है. उस दृष्टिकोण से, एसटी निगम ने एक कदम आगे बढ़ाया है। यात्रियों को यात्रा के दौरान फोन पे, गूगल पे के माध्यम से टिकट खरीदने की सुविधा प्रदान की गई है।

आखिरकार नेशनल हाईवे पर कंक्रीटिंग का काम शुरू...

121 किमी सड़क पर हुई व्हाइट टॉपिंग

वसईः मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग के कंक्रीटिंग कार्य को उसका हक मिल गया है। यह काम सोमवार से विरार के पास खानिवडे से शुरू हो गया है. इसमें करीब 121 किमी सड़क का चरणबद्ध तरीके से कंक्रीटीकरण किया जाएगा। मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग मुंबई, गुजरात के साथ-साथ वसई विरार, पालघर, ठाणे, मीरा भयंदर शहरों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण राजमार्ग है। संचार की दृष्टि से विभिन्न भागों को जोड़ने वाला राजमार्ग होने के कारण वर्तमान में इस सड़क पर वाहनों का भारी आवागमन रहता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस राजमार्ग के रखरखाव एवं मरम्मत पर ध्यान नहीं दिए जाने से विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं। खासकर बरसात के मौसम में यहां गड्ढों की बड़ी समस्या होती है और नागरिकों को यहां से सफर करने में काफी परेशानी होती है।

गड्ढों के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लगातार उत्पन्न हो रही समस्या के कारण नागरिकों की ओर से इसका स्थाई एवं दीर्घकालिक समाधान निकालने की मांग की जा रही थी। हाईवे पर 121 किलोमीटर तक व्हाइट टॉपिंग कर सड़क को कंक्रीट करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए 600 करोड़ का फंड खर्च किया जाएगा और 3 सबवे ब्रिज, 10 पैदल यात्री ब्रिज शामिल किए गए हैं. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की थी कि यह काम सिर्फ एक महीने में शुरू कर दिया जाएगा. लेकिन एक माह बाद भी काम शुरू नहीं हुआ. इसलिए नागरिकों में चर्चा रही कि मंत्री की घोषणा खोखली है. इसके अलावा दैनिक लोकसत्ता ने भी इस सड़क के काम में हो रही देरी को लेकर खबर प्रसारित की और इस मामले को प्रशासन के ध्यान में लाया. आखिरकार शनिवार को सड़क के काम का ट्रायल किया गया और सोमवार से वास्तविक काम शुरू हो गया है।

इसकी शुरूआत विरार के पास खानिवडे टोलनाका से हुई है. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक सुहास चिटनिस ने कहा है कि इस सड़क का कंक्रीटिंग खानीवाडे टोल रोड से चारोटी और खानीवाडे से वसोर्वा ब्रिज तक पूरा किया जाएगा। सोमवार से हाईवे की व्हाइट टॉपिंग शुरू कर दी गई है। सारी योजना चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी।- सुहास चिटनिस, परियोजना निदेशक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

ठाणे में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव... पुलिस को हत्या का शक

ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे जिले में सड़क किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है, जिसके शरीर पर चाकू से कई वार किए जाने के निशान हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने इस संबंध में हत्या का मामला दर्ज किया है। जिला ग्रामीण पुलिस नियंत्रण कक्ष के एक अधिकारी ने बताया कि सोमवार शाम को कुछ राहगीरों ने कल्याण तालुका के कम्बा गांव में सड़क किनारे पड़े एक व्यक्ति के क्षत-विक्षत शव को देखा और उन्होंने स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी। ऐसा माना जा रहा है कि जिस व्यक्ति का शव मिला है उसकी आयु 30 से 35 वर्ष के बीच थी। उन्होंने बताया कि शरीर पर चाकू से हमला किए जाने के कई निशान हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजा है। अधिकारी ने बताया कि कल्याण तालुका पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है और दोषियों की तलाश जारी है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो घोटाले में सीबीआई को ट्रांसफर की सभी FIR... दिल्ली की सीबीआइ कोर्ट में सुनवाई करने का निर्देश

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बिटक्वाइन क्रिप्टोकरेंसी घोटाले से संबंधित कई एफआइआर को आगे की जांच के लिए सीबीआइ को ट्रांसफर कर दिया है। इसके साथ ही इस संबंध में आरोप पत्र भी दायर कर दिया है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पाडीवाला और मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने बुधवार को यह भी निर्देश दिया कि इन मामलों की सुनवाई नई दिल्ली स्थित एक विशेष सीबीआइ अदालत में हो। साथ ही कहा कि आरोपित को अगर अन्य अदालत से नियमित जमानत नहीं मिलती है तो वह दिल्ली हाई कोर्ट जा सकते हैं।

45 एफआइआर दर्ज

खंडपीठ ने 45 एफआइआर पर आरोपित को अग्रिम जमानत संबंधी 30 अगस्त, 2019 के अपने पूर्ववर्ती आदेश को संशोधित करते हुए कहा कि अब यह प्रभावी नहीं है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की रेजिस्ट्री में आरोपित की ओर से जमानत की पूर्व शर्त के तौर पर जमा कराए एक करोड़ रुपये भी दिल्ली स्थित सुनवाई अदालत में स्थानांतरित करने होंगे।

बिटक्वाइन कारोबार के जरिये देश के निवेशकों से धोखा

आरोपित अमित भारद्वाज और अन्य के खिलाफ दर्ज दर्जनों एफआइआर में बिटक्वाइन कारोबार के जरिये देश के निवेशकों से धोखा करने का आरोप सर्वोच्च अदालत में लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि अमित, उसके दो भाई और पिता भी आरोपित हैं। ईडी के मुताबिक देश भर के लोगों को ठगने पर उसके खिलाफ 47 एफआइआर दर्ज हुई थीं। यह मामले में 20 हजार करोड़ रुपये मूल्य के 87 हजार बिटक्वाइन की ट्रेडिंग करने का आरोप है।

अंधेरी में कई कारों में लगी आग... अंदर सो रहा शख्स बुरी तरह झुलसा, अस्पताल में भर्ती

मुंबई : मुंबई के अंधेरी इलाके में तीन कार में आग लग गई. कार में सो रहा एक शख्स बुरी तरह जल गया है. ये घटना अंधेरी के महाकाली गुफा रोड इलाके की है. ये आग रात 02 बजकर 25 मिनट पर लगी थी. आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची. जिन तीन चार पहिया वाहनों (कार) में आग लगी है उसमें से केवल दो की ही पहचान हो पाई है जिसकी जानकारी नीचे दी जा रही है.

1) Mruti Suzuki Wgof R **(MH-03,CP-4780)**

2) Mruti Suzuki Wgof R **(MH-02,EH-3936)**

एक शख्स बुरी तरह घायल

बता दें ये तीनों वाहन Trfs Residefcy buildifg के सामने पार्क की गई थी. रात 02.44 पर आग पर काबू पा लिया गया है. 45 साल के फारूक सिद्दीकी नाम का शख़्स बुरी तरह जख्मी हुआ है. उसका शरीर 90 फीसदी तक जल गया है. इसके बाद उसे बेहतर इलाज के लिए कस्तूरबा हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है.

क्या है पूरा मामला ?

मुंबई के अंधेरी इलाके में बुधवार को तड़के कुछ गाड़ियों में आग लग गई, जिसमें एक व्यक्ति भी झुलस गया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यह घटना अंधेरी (पूर्व) में 'महाकाली केव्स रोड' पर ट्रांस रेजिडेंसी के सामने देर रात करीब दो बजकर 25 मिनट के आसपास की है. दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इस घटना में फारूक सिद्दीकी (45) नाम का एक व्यक्ति झुलस गया और तीन गाड़ियां जलकर खाक हो गईं. उन्होंने बताया कि दमकल की दो गाड़ियों को मौके पर भेजा गया और देर रात दो बजकर 44 मिनट पर आग पर काबू पा लिया गया. एक स्थानीय अधिकारी ने बताया कि सिद्दीकी को पहले नगर निगम द्वारा संचालित अस्पताल ले जाया गया और बाद में आगे के इलाज के लिए सतरस्ता के कस्तूरबा अस्पताल में भर्ती कराया गया . आग लगने के कारण का फिलहाल पता नहीं चल पाया है.

ट्रैफिक जुमार्ने की राशि में कमी, वसूली बढ़ी

ठाणेः पुलिस विभाग ने ठाणे पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर ई-चालान प्रक्रिया के माध्यम से लगाए जाने वाले जुमार्ने को 30 से 40 प्रतिशत तक कम करने का निर्णय लिया है। इस फैसले के सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं और महज नौ दिनों में परिवहन विभाग को डेढ़ करोड़ रुपये का जुमार्ना अदा किया गया है. ठाणे से बदलापुर और भिवंडी शहर तक, ठाणे यातायात पुलिस द्वारा ई-चालान मशीन के माध्यम से यातायात उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। यह अनुभव किया गया है कि ई-चालान के माध्यम से लगाए गए जुमार्ने की राशि का पर्याप्त भुगतान नहीं किया जाता है। ठाणे पुलिस ने बकाया जुमार्ना राशि वसूलने के लिए अंतरिम अभियान चलाया है। इस राशि को 30 से 50 फीसदी तक कम करने का निर्णय लिया गया. लोक अदालत के माध्यम से नोटिस भी भेजे गए। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि आगामी फरवरी माह में लोक अदालत के लिए भी इसी तरह का अभियान चलाया जाएगा.

अतिदेय जुमार्ने की वसूली को चुनौती

चूंकि अतिदेय ई-चालान कार्रवाई में जुमार्ना राशि का भुगतान कभी भी किया जा सकता है, इसलिए वाहन चालक जुमार्ना राशि को नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए अगर वाहन चालक दोबारा यातायात नियमों का उल्लंघन करता है तो जुमार्ने की राशि बढ़ जाती है. बकाया जुमार्ना राशि वसूलने में ठाणे पुलिस पिछड़ गई है। कमिश्नरेट क्षेत्र में 31 लाख 71 हजार से अधिक वाहनों पर कार्रवाई की गयी है. लेकिन बकाया जुमार्ने की रकम 198 करोड़ रुपये है. ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाता है। इनमें से कई मामले लंबित हैं. इन लंबित मामलों का निपटारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की लोक अदालत के माध्यम से किया जाता है।

करीब एक माह पहले लोक अदालत की पृष्ठभूमि में मुख्य दंडाधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव, सिविल जज, पुलिस उपायुक्त डॉ. विनय कुमार राठौड़ के साथ बैठक हुई. इसके बाद ऐसे मामलों में समझौता कराने के लिए सहायता केंद्र शुरू करने का निर्णय लिया गया. इसके लिए तीन हाट नाका स्थित ठाणे परिवहन शाखा के कार्यालय में एक सहायता केंद्र शुरू किया गया। इस सहायता केंद्र को बकाया जुमार्ने वाले मोटर चालकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है।

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। संपर्क कार्यालय : शॉप नंबर ४ , मदीना मेंशन, ८१ ए, कैडल रोड, अपोजिट बिल्लाबोंग स्कूल, माहिम पश्चिम, मुंबई ४०००१६ , महाराष्ट्र मोबाइल नं 998777 5650 व्हाट्सप्प नं 7977408589: Email-editor@rokthoklekhaninews.com